(ग) कोयला और अन्य खनिजों की रायल्टी दरों में संशोधन न किए जाने से हानि निम्नलिखित कारणों से काल्पनिक है–

(1) अधिनियम में हर तीन वर्ष की समाप्ति पर वृद्धि करना आदेशात्मक प्रावधान नहीं है; और

(2) यदि रायल्टी दरों में पहले संशोधन किया गया होता तो ये दरें बाद में अधिसूचित दरों से भिन्न होतीं।

(घ) केन्द्र सरकार, प्रधान खनिजों की रायल्टी दरें अधिसूचित करती है, किन्तु यह राशि राज्य सरकारों द्वारा सीधे ही पट्टाधारकों से वसूल की जाती है और इसलिए, केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को रायल्टी की राशि जारी करने का प्रश्न नहीं उठता।

Exploration of minerals

326. SHRI S. MADHAVAN: Will the Minister of MINES be pleased to state:

(a) whether thare is any proposal to permit the mining companies abroad to undertake mineral exploration activities in India; and

(b) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF MINES (SHRI BALRAM SINGH YADAV): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

सोने की खोज

327. **श्री राम नरेश यादव :** क्या **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में स्वर्ण खानों से सोने का पता लगाने के लिए विदेशी मशीनों का किन-किन स्थानों पर प्रयोग किया गया था ;

(ख) इन यंत्रों का उपयोग करने से कितनी सफलता मिली है और कितना सोना प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) उपलब्धों जानकारी के अनुसार, देश में स्वर्ण खानों मे सोने का पता लगाने के लिए विदेशी मशीनों का प्रयोग नहीं किया गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता

Allocation of Steel to Arunachal Pradesh

328. SHRI NYODEK YONGGAM: Will the Minister of STEEL be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have made allocation of steel and C.G.I. sheets to Arunachal Pradesh during 1989-90, 1990-91 and 1992 so far;

(b) if so, the details thereof;

(c) what is the total quantum of each quota;

(d) whether such quota is directly collected by the State Government; and

(e) if so, the details thtreof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF STEEL (SHRI SONTOSH MOHAN DEV): (a) to (c) Supply of various steel items including galvanised sheets are made by the main producers to Arunachal Pradesh on the basis of supply plans made by the Development Commissioner for Iron and Steel in favour of the nodal authority (for Government Departments, PSUs, etc.) and allocations in favour of the Arunachal Pradesh Industrial Development and Financial Corporation Limited (for small scale industries). The year-wise